

152 खोए मोबाइल लौटे, कंट्रोल रूम बना खुशियों का मंच

नवभारत न्यूज़ खंडवा। मंगलवार का दिन कई परिवारों के लिए खुशियों की सीगात लेकर आया, जब खंडवा पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 152 गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए। बरामद किए गए मोबाइलों की कुल कीमत करीब 22 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित मोबाइल वितरण कार्यक्रम के दौरान जैसे ही लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस मिले, वहां खुशी और उत्साह का माहौल बन गया। लंबे समय से मोबाइल गुम होने की परेशानी झेल रहे लोगों के चेहरे खिल उठे। कई लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अगुवाई पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने की। उन्होंने स्वयं नागरिकों को उनके



मोबाइल फोन सौंपे और साइबर सेल व तकनीकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक और सतत प्रयासों के जरिए गुम हुए मोबाइलों की रिकवरी संभव हो पाई है। साइबर सेल की टीम ने विभिन्न जिलों और राज्यों में सक्रिय रहकर मोबाइल

फोन को तकनीकी सहायता से ट्रेस किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया से मोबाइल की बरामदगी की जा सके। खंडवा पुलिस की यह पहल जनसेवा, तकनीकी दक्षता और आधुनिक पुलिसिंग का एक सकारात्मक उदाहरण बनकर सामने आई है।

गुलगुली नाला सफाई अभियान शुरू



नवभारत न्यूज़ खंडवा। नगर निगम खंडवा द्वारा मंगलवार को गुलगुली नाला सफाई अभियान के तहत वार्ड क्रमांक अमर शहीद अशफाक उल्लाह (खारी बावड़ी) क्षेत्र से विशेष सफाई कार्य प्रारंभ किया गया। अभियान के अंतर्गत 10 श्रमिकों की टीम नाले की तलहटी से मैनुअली गाद और कचरा निकाल रही है। नगर निगम के अनुसार सफाई कार्य ऊंट कुआं से खारी बावड़ी, हटई इमामबाड़ा

होते हुए छठी माता क्षेत्र तक किया जाएगा। यह नाला दो वार्डों से होकर गुजरता है, जहां लंबे समय से सफाई की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अभियान के दौरान अब तक करीब 3 ट्राली मलबा और कचरा निकाला जा चुका है। नगर निगम ने बताया कि बरसात से पहले जलभराव की स्थिति रोकने और स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

252 करोड़ की ड्रेनेज परियोजना में अनियमितताओं के आरोप

कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने किया मौका मुआयना

नवभारत न्यूज़ खंडवा। शहर में 252 करोड़ रुपये की लागत से संचालित ड्रेनेज परियोजना अब गंभीर सवाल के घेरे में आ गई है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर लगातार अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने निर्माण स्थल का मौका मुआयना कर कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर आपत्ति जताई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना में कई स्थानों पर टूटे हुए और क्षतिग्रस्त पाइपों का उपयोग किया जा रहा है।

साथ ही पाइप लाइन डालने से पहले बेस सिस्टम भी तकनीकी मानकों के अनुरूप तैयार नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि पाइप जॉइनिंग के दौरान सीमेंट और अन्य सामग्री को मात्रा कम



रखी जा रही है, जिससे निर्माण कार्य की मजबूती और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही है। प्रतिभा

रघुवंशी ने कहा कि करोड़ों रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में यदि इसी तरह लापरवाही बरती गई तो आने वाले समय में सड़क धंसने, पाइप लाइन लीकेज, सीवरेज ओवरफ्लो और जलभराव जैसी गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा और जनता के टैक्स के करोड़ों रुपये भी व्यर्थ चले जाएंगे। उन्होंने निर्माण एजेंसी से मांग की कि पूरे कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए तथा गुणवत्ता से समझौता करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते निर्माण कार्य में सुधार नहीं किया गया तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर व्यापक आंदोलन करेगी। स्थानीय नागरिकों ने भी परियोजना की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताते हुए प्रशासन से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है।

जनसुनवाई में गुंजी पेंशन, राशन और भ्रष्टाचार की शिकायतें

नवभारत न्यूज़ खंडवा। कलेक्टर ऋषव गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में जिले भर से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस जनसुनवाई में पेंशन भुगतान, राशन वितरण, पंचायतों में भ्रष्टाचार, सिंचाई परियोजना की अनुपयोगी सामग्री हटाने तथा मजदूरी दर बढ़ाने जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों सामने आए। जनसुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त विकासखंड अधिकारी प्रतापसिंह मुवेल ने फरवरी 2024 में रिटायर होने के बावजूद पेन्शन नहीं, जीपीएफ और पेंशन स्ट्रेन्ड नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर कलेक्टर ने जिला पंचायत अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई



कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खालवा तहसील के ग्राम चिकतलाई निवासी मिथुन काजले ने राशन कार्ड पर मुफ्त खाद्यान्न नहीं मिलने की समस्या बताई, जबकि पंधाना विकासखंड की ग्राम पंचायत डोंगरगांव के ग्रामीणों ने पंचायत में निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच की मांग रखी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम रेवाड़ा के

नानकराम ने उद्दहन सिंचाई परियोजना की अनुपयोगी सामग्री हटाने की मांग की। दूसरी ओर पंधाना रोड स्थित सब्जी मंडी के हम्मालों ने बढ़ती महंगाई के बीच मजदूरी दर बढ़ाने की मांग प्रशासन के सामने रखी। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर केआर बड़ोले, सहायक कलेक्टर शिल्पा चौहान तथा सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

मोहद रोड निर्माण बना परेशानी का कारण

नवभारत न्यूज़ बीड। मोहद रोड निर्माण कार्य के चलते अस्थायी रूप से शिवरिया रोड पर शिफ्ट किया गया बीड का साप्ताहिक बाजार अब ग्रामीणों और व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। शुरुआत में प्रशासन द्वारा बाजार को केवल 3 से 4 हफ्तों के लिए हटाने की बात कही गई थी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी बाजार अपने पुराने स्थान पर वापस नहीं पहुंच पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि बाजार तक पहुंचने के लिए अब उन्हें करीब एक किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। खरीदारी के बाद भारी सामान लेकर लौटना भीषण गर्मी और तेज हवाओं के बीच बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा

महीनों से शिवरिया रोड पर लग रहा बीड का साप्ताहिक बाजार



है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सवाल किया है कि जब बसों का संचालन पहले की तरह पुराने मार्ग से किया जा रहा है, तो फिर बाजार को उसके मूल स्थान पर लगाने में क्या दिक्कत है। ग्रामीणों के अनुसार अस्थायी व्यवस्था अब स्थायी समस्या का रूप ले चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने 3-4 हफ्तों का आश्वासन दिया था, लेकिन लंबे समय बाद भी बाजार शिवरिया रोड पर ही लगाया जा रहा है। इससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।

व्यापारियों की बड़ी चिंता- बाजार का स्थान बदलने से स्थानीय व्यापारियों के कारोबार पर भी सीधा असर पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों की संख्या कम हो गई है, जिससे उनकी रोजाना की आमदनी प्रभावित हो रही है। वहीं आसपास के क्षेत्र से आने वाले

किसान, किराना व्यापारी और अन्य दुकानदारों ने आरोप लगाया कि पहले प्रत्येक दुकान से 30 रुपये शुल्क लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 50 रुपये कर दिया गया है। हाथ ठेला लगाने वालों का कहना है कि उनसे पहले 20 रुपये लिए जाते थे, जबकि अब 30 रुपये वसूले जा रहे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि पंचायत द्वारा दुकान शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई है।

क्या बोले जिम्मेदार-

ग्राम पंचायत सचिव प्रकाश चौहान ने बताया, मोहद रोड का निर्माण कार्य पूरा होने तक बाजार को पुराने स्थान पर नहीं लगाया जा सकता। हमें तहसीलदार मैडम के निर्देश प्राप्त हैं और उसी के अनुसार व्यवस्था संचालित की जा रही है।

किलौद बस स्टैंड चौराहे पर गंदगी से लोग परेशान



नवभारत न्यूज़ किलौद। क्षेत्र के बस स्टैंड चौराहे स्थित सरकारी कुएं के आसपास फैली गंदगी से आमजन परेशान हैं। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि कुएं में लंबे समय से गंदगी जमा होने के कारण वहां से गुजरना तक मुश्किल हो गया है। प्रतिदिन करीब 21 पंचायतों और आसपास के गांवों से आने-जाने वाले लोगों को बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कुएं के आसपास सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। गर्मी बढ़ने के साथ स्थिति और गंभीर हो गई है। शाम 5 बजे के बाद क्षेत्र में बदबू इतनी अधिक फैल जाती है कि लोगों का वहां खड़ा होना तक मुश्किल

हो जाता है। लोगों का आरोप है कि सरपंच और सचिव की लापरवाही के कारण समस्या लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार इस संबंध में कई बार जनपद पंचायत में शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने मांग की है कि तत्काल कुएं और आसपास के क्षेत्र की साफ-सफाई कराई जाए। यदि कुएं का उपयोग नहीं हो रहा है तो उसे सुरक्षित तरीके से बंद किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना या बीमारी फैलने का खतरा न रहे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने की मांग की है।

ओंकारेश्वर पावर स्टेशन में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ

नवभारत न्यूज़ ओंकारेश्वर। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनएचडीसी लिमिटेड के निगम मुख्यालय के दिशा-निर्देशानुसार ओंकारेश्वर पावर स्टेशन में 16 मई से 31 मई तक आयोजित किए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ उत्साह और जनभागीदारी के साथ किया गया। अभियान के तहत प्रशासनिक भवन कार्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता जागरूकता से संबंधित बैनर और पोस्टर लगाए गए। इनका उद्देश्य कर्मचारियों, आगतुकों एवं रहवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना तथा परिसर को स्वच्छ एवं हरित बनाए रखना है। कार्यक्रम का शुरुआत परियोजना प्रमुख डीके द्विवेदी एवं महाप्रबंधक (सिविल) संजय कुमार के पुष्पगुच्छ स्वागत के साथ हुई। इसके बाद परियोजना प्रमुख डीके द्विवेदी ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता की शायद दिलाई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा



कि स्वच्छता केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि हमारी दैनिक जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सभी कर्मिकों से अपने कार्यस्थल, निवास स्थान एवं आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाए रखने की अपील करते हुए इस पखवाड़े को प्रेरणादायी जनअभियान के रूप में सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण बनाए रखने का संकल्प लिया। इसके

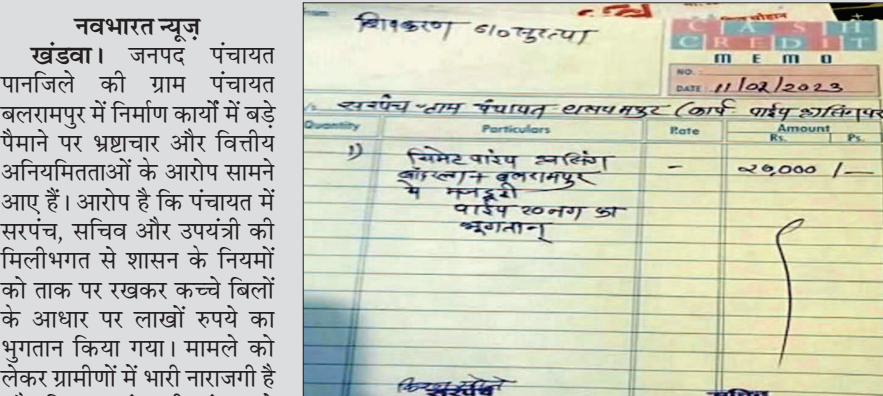
पश्चात ऊर्जा विहार परिसर में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें कचरा संग्रहण, साफ-सफाई एवं स्वच्छ वातावरण बनाए रखने हेतु विशेष गतिविधियां आयोजित की गईं। साथ ही परियोजना चिकित्सालय परिसर में भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर संपूर्ण परिसर की सफाई की गई। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष (आईटी) मनोज नारायण राव चुगे, विभागाध्यक्ष (मानव संसाधन)-प्रभारी नवाब खान, उप महाप्रबंधक (मानव

संसाधन) राजीव शर्मा, विभागाध्यक्ष (वित्त) भूपेश बर्तुनिया, विभागाध्यक्ष (सीएण्डपी) राजेश कुमार, विभागाध्यक्ष (विद्युत कॉलोनी) दिलीप कुर्रे, समूह वरिष्ठ प्रबंधक (भू-विज्ञान) निर्मल कुमार यादव, समूह वरिष्ठ प्रबंधक (विद्युत) भानु प्रताप पाल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी विशालाक्षी मुदुल, प्रमोद कुमार सिंह, ब्रजेश खड़ावते एवं विनोद सेन सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी एवं ठेका श्रमिक उपस्थित रहे।

एक नजर

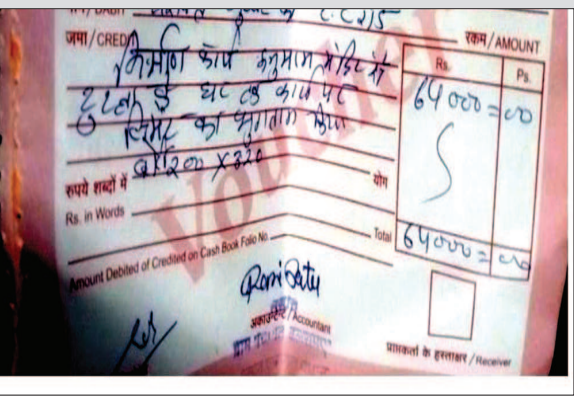
ग्राम पंचायत बलरामपुर में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

कच्चे बिलों से लाखों के भुगतान पर उठे सवाल



नवभारत न्यूज़ खंडवा। जनपद पंचायत पानजिले की ग्राम पंचायत बलरामपुर में निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि पंचायत में सरपंच, सचिव और उपयंत्री की मिलीभगत से शासन के नियमों को ताक पर रखकर कच्चे बिलों के आधार पर लाखों रुपये का भुगतान किया गया। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है। जानकारी के अनुसार हनुमान मंदिर से टूटला के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य के लिए 1 लाख 98 हजार 400 रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। कार्य की स्वीकृति टीएस नंबर 656 दिनांक 27 फरवरी 2017 के तहत दी गई

थी। आरोप है कि निर्माण कार्य में 200 बोरी सीमेंट की खरीदी 320 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से दर्शाकर 64 हजार रुपये का भुगतान किया गया, जबकि संबंधित बिल कच्चा बताया जा रहा है। इसी प्रकार गिट्टी और रेत खरीदी के नाम पर भी हजारों रुपये का भुगतान किया गया। सभी भुगतान एक ही दिन 25 मार्च 2019 को यूपीआर नंबर स65774488 के माध्यम से किए गए, जबकि आज तक कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। इससे अलावा बंदरला में पक्की नाली एवं पाइप क्रॉसिंग



निर्माण कार्य में भी गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। 51 हजार रुपये की स्वीकृत राशि वाले इस कार्य में पंचायत द्वारा 13 फरवरी 2023 को ही पूरी राशि खर्च दर्शा दी गई। आरोप है कि बिना पर्याप्त सीमेंट, रेत और गिट्टी के ही निर्माण कार्य का भुगतान कर

दिया गया। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब राशि खर्च हो चुकी तो अब तक कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ और उपयंत्री द्वारा किस आधार पर मूल्यांकन किया गया। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।